International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

ग्रामीण भारत में कौशल विकास कार्यक्रम : एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण

प्रो.आशुतोष व्यास[1] राधेश्याम गमेती[2]

[1] सह आचार्य समाजशास्त्र राजकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय चित्तौडगढ
[2]मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय उदयपुर

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता से सम्बन्धित प्रयास अब तक हमारे देश में बिखरे हुए रहे हैं। विकसीत देशों में जहां कुशल कार्यबल का प्रतिशत कुल जनसंख्या का 60 से 90 प्रतिशत के बीच हैं। इसके विपरीत भारत के कार्यबल का स्तर औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा के साथ 4.69 प्रतिशत के निचले स्तर पर हैं। आज भारत में बेरोजगार लोंगों के जीवन की बेहतर गुणवता के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता संवर्धन के परिस्थतिकी तंत्र को तेजी से पुर्नगठित करने की आवश्यकता हैं ,जो उद्योगों की आवश्यकता को पूरा करने के साथ–साथ देश के लोगों के जीवन की गुणवता को समर्थ बनाने में अपना योगदान दे।

कौशल एवं ज्ञान किसी भी देश के लिए आर्थिक प्रगति और सामाजिक विकास की प्रेरक शक्तियां हैं। कौशल का उच्च–स्तर और बेहतर मानक वाले देश घरेलू एवं अतंराष्ट्रीय रोजगार बाजार में चुनौतियां और अवसरों का अधिक प्रभावशाली ढंग से समायोजित करते हैं। स्वतंन्त्रता के 68 वर्ष पश्चात् भारत में पहली बार कौशल को रोजगारपरक बनाने की कोशिश हुई, और इसके परिणामस्वरूप कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंन्त्राालय का गठन हुआ, ताकि भारत में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाए तथा गरीबी अशिक्षा आतंकवाद जैसी–समस्यांओं का सफलतापूर्वक निदान किया जाए। भारत की 75 पतिशत जनसंख्या गावों में निवास करती है और ग्रामीण जनता ज्यादातर कृषि–आधारित व्यवसायों पर निर्भर रहती हैं। असली भारत आज भी ग्रामीण परिवेश में कृषि एवं पशुपालन जैसे परम्परागत कार्यों में संलग्न हैं। और गरीबी अशिक्षा से लगातार संघर्ष करते हुए राष्ट्र के निर्माण में मानव संसाधन के रूप में योगदान कर रहें हैं। आज विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा करना है तो इन गावों में रहने वाली जनसंख्या को मुलभूत सुविधाएं प्रदान करने इनका सही मार्गदर्शन करना होगा. वर्तमान में भारत की 35 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या, कुल जनसंख्या का 65 प्रतिशत है, ये युवा भारत का सपना साकार करने का यह सही वक्त हैं। इनका उपयोग राष्ट्र निर्माण के लिए करने हेतु कौशल भारत–कुशल भारत योजना की शुरूआत भारत सरकार ने विश्व कौशल 15 जुलाई 2015 को एक मिशन के रूप में की । भारत सरकार का लक्ष्य इस मिशन के द्वारा 2022 तक बेरोजगार युवाओं का रूचि अनुसार कौशल विकास करके रोजगारपरक बनाना था।

कौशल विकास के मामले में हमारा देश दुसरे देशों से काफी पीछे है। नेश्नल सेम्पलसर्वे के अनुसार भारत में कौशल विकास 3.5 प्रतिशत हैं। और 2019 तक भारत को 12 करोड कौशल युवाओं की जरूरत होगी पहले वर्षों में लगभग लाख शहरी व ग्रामीण युवाओं को इस योजनाओं के तहत लाख सरकार का लक्ष्य 2022 तक यह संख्या 40 करोड से उपर ले जाने का है। तथा साथ ही यह भी निर्धारित किया जाना है, कि देश अन्दर युवाओं को विधिवत कौशल विकास की शिक्षा के लिए कौशल विश्वविद्यालयों की स्थापना प्रेत्यक राज्य में की जाए।

कौशल विकास योजना के उद्देश्यः–

देश में गरीबों का उन्नमूलन कर अधिक से अधिक युवाओं को शिक्षित कर उन्हें रोजगार दिलाना है। इसके अलावा इस मिशन का उद्देश्य विकास के नये क्षेत्रों को ढूंढकर उन्हें विकसीत करने का प्रयास करना हैं। कौशल विकास योजना के उद्देश्य निम्न प्रकार है–

- गरीब बच्चे जो उच्च शिक्षा लेने से वंचित रह जाते हैं, उनके अन्दर छुपे हुए कौशल को पहचानना।
- अधिक से अधिक युवा शक्ति के हुनर को पहचानना और उन्हें उनकी योग्यता के मुताबिक रोजगार दिलाना।
- गरीबी एवं अशिक्षा को दुर करने के अलावा गरीब परिवारों और युवाओं में कौशल विकास करना और उन्हें आगे बढाने का आत्म विश्वास दिलाना।
- युवाओं को तकनीकी शिक्षा के साथ–साथ कम्प्यूटर शिक्षा देना ।
- कौशल विकास के साथ–साथ उद्यमिता और मूल्य सवंर्धन को बढावा देना।
- सभी तकनीकी संस्थाओं को विश्व में बदलती तकनीकी के अनुसार गतिशील बनाना।
- भारतीय बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर रोजगारपरक बनाकर राष्ट्र के विकास एवं राष्ट्र की मुख्यधारा में सम्मिलित करना।

भारत में कौशल विकास की आवश्यकता क्यों:–

भारत को विकसीत राष्ट्र बनाने के लिए अनेक कार्यक्रमों को शुरू किया गया हैं। और विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं को कौशल विकास योजना के साथ जोड़ा गया, जिससे खासकर ग्रामीण एवं गरीब युंवाओं का पूर्ण विकास किया जा सकें। भारत सरकार कि मेक इन इण्डिया, डिजिटल इंण्डिया एवं स्मार्ट सिटिज जैसी महत्वकाक्षी योजनाओं को सफल बनानें के अलावा अन्य आवश्यकताएं इसलिए उत्पन्न हुई–

1.चीनी आर्थिक विकास दर धीमी होना एक अच्छा अवसर।
2.कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढाया जा सकें।
3.कौशल पुंजी में भारत विश्व स्तर पर गुणवता बनाए।
4.अच्छे रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें।
5.भारत को विश्व कौशल की राजधानी बनाना।

कौशल परिवेश की रूपरेखा: –

विश्व के सबसे बड़े मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के तहत भारत की मानव श्रम शक्ति में प्रत्येक महिने 10 लाख की वृद्वि हो रही हैं। इसी के आधार पर भारत के कौशल परिवेश के लिए 10 बिन्दुओं वाली रूप रेखा तैयार की गई हैं।

- तेज गति से व्यापक विस्तार एवं प्रसार।
- गुणवतापुर्ण परिणाम पर बल।
- मानक से जुडकर कौशल का विकास करना।
- सभी जातिवर्गो में कौशल विकास पर बल।
- विश्व में कहीं भी कार्य करने योग्य बनानें का प्रयास।
- कौशल क्षैत्र के सभी प्रयासों समेटते हुए उनमें समन्वय स्थापित करना।
- कुश्लता के महत्वकांक्षा से जोड़ने की पहल।
- उद्योग जगत से जुड़ाव पर बल।
- शिक्षण एवं प्रशिक्षण के बीच अर्तसंम्बध स्थापित ।
- तकनीकी के उपयोग पर बल।

ग्रामीण भारत में कौशल विकास को बढावा देने हेतु प्रमुख कार्यक्रम एवं योजनाएँ–

1.स्टार्टअप इंडिया:– 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई यह पहल मजबूत स्टार्टअप इको–सिस्टम व संस्कुति को बढावा देने, उद्यमियों की सहायता प्रदान करने के साथ–साथ देश में नौकरी की मांग करने वालों के बजाय नौकरी देने वालों को विकसित करना हैं । इसके अन्तर्गत स्टार्टअप हेतु आसान अनुपालना स्टार्टअप बंद करने व अन्य कानुनी सहायता अनुदान व प्रोत्साहन इत्यादि शामिल हैं।

2.स्टैंडअप इंडिया:– यह योजना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ महिलाओं के नए/ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने हेतु कम से कम एक महिला उधारकर्ता को प्रति बैंक शाखा 10 लाख से लेकर 1 करोड रूपये तक के बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करती है। जो विनिर्माण सेवाओं या व्यापारिक क्षेत्र में हो सकता है।

3.प्रधानमंत्री मुद्रा योजना:– 8 अप्रेल 2015 को शुरू की गई यह योजना गैर कॉर्पोरेट गैर–कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को शिशु (50 हजार तक का ऋण) किशोर (5 लाख तक का ऋण) और तरूण (10 लाख तक का ऋण) का ऋण प्रदान कर नए उद्यम विकसीत करने की दिशा में प्रयास है। ये ऋण वाणिज्यिक बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लघु वित् बैंक एमएफआई और एनबीएफसी द्वारा दिए जाते हैं।

4.अटल इनोवेशन मिशन:–इनक्यूबेशन सेंटर–तकनीकी व नवाचार उद्यमों /स्टार्टअप को विकसीत करने में सहायता प्रदान करना जिसके अन्तर्गत व्यावसायिक नियोजन बाजार में प्रवेश व वित्तिय मामलों से संबंधित सलाह इत्यादि।

5.प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना:–2015–16 में युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण देकर बेहतर रोजगार योग्य बनाने की दिशा में पहला कदम था। इसके बाद योजना(2.0) के तहत वृहद् रूप से दुसरी बार 2016–20 के मध्य एक करोड युवाओं को नि:शुल्क 2 से 6 महिने तक प्रशिक्षण प्रदान कर कुशल बनाने की दिशा में प्रयास किया गया। **6.संकल्प:–**विश्व बैंक कि सहायता से चलाए ला रहें इस कार्यक्रम का उद्देश्य कौशल विकास एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य–स्तरीय

संस्थाओं को मजबूत बनाने समाज के वंचित वर्ग को कौशल शिक्षा व प्रशिक्षण के साथ–साथ विनिर्माण क्षेत्र में आवश्यक कुशल मानव संसाधनों को विकसीत कर मेक इन इण्डिया पहल में सहायता करना है।

7.दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजनाः–15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को समर्पित यह योजना सरकार के सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों जैसे मेक इन इंडिया डिजिटल इंडिया स्मार्ट सिटीज और स्टार्टअप इंडिया स्टैडअप इंडिया अभियानों से संबंधित हैं। ग्रामीण युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर श्रमशक्ति बाजार के अनुरूप तैयार करने की प्लेसमेंट से जुडी कौशल विकास की यह सशक्तिकरण योजना है।

8 महिला किसान सशक्तीकरण योजना–

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और एनजीओं द्वारा संचालित इस योजनाओं में स्थायी कृषि, गैर इमारती वन उत्पाद और बाजार सम्पर्क की स्थापना पर बल दिया गया। इस योजना द्वारा देश में 2015–16 में 119 जिलों की 30.65 लाख से अधिक महिला किसान लाभान्वित हुई

9 प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फेलो योजना–

समेकित कार्ययोजना वाले जिलों में दुर्गम व चुनौतीपुर्ण परिस्थितियों में कार्य के लिए होनहार युवा व्यवसायियों को क्षमता निर्माण अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारम्भ की गई। इसका संचालन कपार्ट द्वारा 2016–17 से किया जा रहा हैं।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षैत्रों में भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन, सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑन रूरल लाइवलीहुड, स्टार्टअप ग्रामीण उद्यम कार्यक्रम, कृषि में कौशल विकास हेतु व्यवसाय विशेष के लिए समर्पित संस्थान युवाओं को उद्यम प्रशिक्षण और कौशल प्रदान हेतु चलाए जा रहे हैं।

ग्रामीण भारत में कौशल विकास की दशा एवं दिशाः–

ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास का स्तर काफी निम्न हैं। परंपरागत तौर पर गांवों में हस्तशिल्प और दस्तकारी जैसे कौशल को औपचारिक शिक्षा में न जोडने के कारण यह स्तर उठ नहीं पाया। वहीं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का केन्द्रीकरण भी उन्हीं शहरी क्षैत्रों के आस–पास रहा जहां उद्योग–धन्धें थे। इसलिए ग्रामीण भारत का बडा भाग कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा से वंचित रह गया । नेशल सैम्पलसर्वे ऑफिस की एक रिपोर्ट–भारत में शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की स्थिति के अनुसार वर्ष 2011–12 में देश में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों में केवल 2.4 प्रतिशत के पास ही तकनीकी डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट था। यह अनुपात ग्रामीण क्षेत्र में 1.1 प्रतिशत और नगरीय क्षैत्रों में 5.5 प्रतिशत है।

इस से भी चौकाने वाले तथ्य यह हैं– कि व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे लोगों का आंकडा अभी काफी कम है। वर्ष 2011–12 में देश में मात्र 0.9 प्रतिशत लोग ही व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। गॉवों मे तो यह स्तर आधा प्रतिशत ही हैं। इस तरह यह रिपोर्ट ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण की चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। बहराल ग्रामीण क्षेत्रों में पुरूषों ने जो औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया उसमें 22 प्रतिशत ने ड्राइविंग और मोटर एवं मोटर मेकेनिक कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। वहीं महिलाओं में 32.2 प्रतिशत ने वस्त्र से जुड़े कार्यों के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया । वर्तमान में कम्प्यूटर प्रशिक्षण की और भी ग्रामीण युंवाओं का झुकाव देखा गया है। इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक तौर पर दिए जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्यर्यक्रमों में कोई खास विविधता भी नहीं रहीं है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण में गति लाना अब भी बडी चुनौती है। यह कार्य इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण का सबसे ज्यादा अभाव उन राज्यों में है जो आर्थिक और मानव विकास के मानकों पर पिछडे हुए हैं। इन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय का स्तर भी काफी कम है।

वर्तमान में सरकार ने कौशल विकास को प्राथमिकता देते हुए देश में एक अलग कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना की है। साथ ही व्यापक स्तर पर युवाओं के कौशल विकास पर बल देते हुए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी शुरू की है। सरकार के अनुसार इस योजना के तहत बीते दो साल में 1.17 करोड युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका हैं। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने कौशल विकास को औपचारिक शिक्षा से जोडने के एक अनुठी पहल की हैं। सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की तर्ज पर देश में पहले भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना कानपुर में की गई हैं। इस संस्थान की अवधारणा सिंगापुर के तकनीकी शिक्षा संस्थान के आधार पर तैयार की गई है। सरकार ने भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनानें का विजन रखा है, साथ ही सरकार ने अप्रेंटिस से संबंधित कानुन में भी समुचित बदलाव कर कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं के लिए अप्रेंटिस के अवसर बढाने की दिशा में भी कदम उठाया है।देश में तकरीबन 8 लाख कंपनिया पंजीकृत है, जबकि मात्र 23000 ही अप्रेंटिस की सुविधा दे रहीं है। अप्रेंटिस की व्यवस्था से कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को लाभ पहुंचा है। यही वजह हैं, कि सरकार ने इससे जुडे कानून में जरूरी बदलाव करते हुए वर्ष 2016–17 में पांच लाख युवाओं को अप्रेंटिस करवाने का लक्ष्य रखा था।

निष्कर्ष

देश में बेरोजगारी और बैगारी की समस्या को दुर करने व आय का स्तर उठाने और क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर देने की जरूरत है। इस दिशा में मौजूद प्रयासों के साथ–साथ सरकार को कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने और अर्थव्यवस्था के अलग–अलग क्षेत्रों में तेजी से हो रहे बदलावों के अनुरूप ढालना होगा। वर्तमान में विश्व में **इंडस्ट्री 4.0** की लहर चल रही हैं। विकसित देशों में तेजी से उद्योगों में आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस अपनाकर उत्पादन प्रक्रिया को स्वचालित किया जा रहा है। इसी को **इंडस्ट्री 4.0** नाम दिया गया है। इससे विनिर्माण उघोग में रोजगार के अवसर सीमित होने की संभावना है। ऐसे में कौशल विकास औद्योगिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि हमारे युवा आज के उद्योगों की जरूरत के अनुसार कुशल और रोजगार के लायक हों। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकता संसाधनों और परंपरागत ज्ञान को घ्यान में रखकर हमें कोर्स की विषयवस्तु तैयार करनी होगी, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जरूरत के हिसाब से भी कुशल श्रमबल तैयार किया जा सकें। दूरदराज के क्षेत्रों में युवाओं तक पहुंचने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर ऑनलाइन पाठ्सक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना होगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सार्वजनिक– निजी भागीदारी के आधार पर बेहतर बनानें और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में नए आईटीआई खोलने पर जोर दिया जाए । ग्रामीण भारत में कौशल विकास से सम्बन्धित कुछ चुनौतियॉ भी हैं जैसे– आधार भूत संरचना का अभाव, कुशल प्रशिक्षण की कमी, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा सम्बन्धी चुनौतियॉ, अंसगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा, उद्यम स्थापना में जोखिम से निपटने हेतु आवश्यक ज्ञान, कौशल, संसाधन व्यावसायिक शिक्षा का अभाव इत्यादि। स्पष्ट हैं, कि कौशल विकास कार्यक्रम की सफलता हेतु इन चुनौतिया को ध्यान में रखने की आवश्यकता हैं। तभी युवाओं को कौशल विकास के बल पर विश्व स्तर पर भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में खडा किया जा रहा सकता हैं। ग्रामीण क्षैत्र के युवा भी कौशल विकास की योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकेगें तथा उनमें आत्मविश्वास भी उत्पन्न होगा, यही आत्मविश्वास आने वाले समय में आत्मनिर्भर एवं शक्तिशाली विकसित भारत के रूप में दिखाई देगा।

सन्दर्भ सूची–

- मिश्रा अशोक कुमार ग्रामीण विकास खादी ग्रामाद्योग मुम्बई
- कुमार संजीव कौशल विकास योजना का अवलोकन कुरूक्षेत्र 2017
- शर्मा हरिकिशन कौशल विकास एवं रोजगार कुरूक्षेत्र 2017
- टाईम्स ऑफ इंडिया
- द हिन्दू 2012 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रक्रिया पुस्तक,योजनाएं खण्ड 1.2–साईट फिक्की ल फॉर ऑल, न्यू एप्रोचेज ऑफ स्किलिंग इण्डिया, फिक्की स्किल डवलपमेन्ट फॉरम एण्ड सिटी गिल्डस, मनीपाल ग्लोबल.
- योजना आयोगः टूवेल्थ फाइव इयर प्लान, एम्प्लाएबिलिटी एण्ड स्किल डवलपमेंट